HITAVADA, Raipur, 9.1.2022
Page No. 2, Size:(29.43)cms X (10.50)cms.

NHRC expresses concern over living conditions of Mumbai slum dweller

NEW DELHI, Jan 8 (PTI)

THE National Human Rights Commission has expressed concern over the living conditions of slum dwellers in Mumbai and sought a "comprehensive report" from the Centre, officials said on Friday. In a statement, the NHRC said that acting on a complaint in this connection, it had issued notices to the Government of Maharashtra and the Union Ministry of Housing and Urban Affairs seeking their responses.

The Government of Maharashtra responded, through its Chief Secretary, that several efforts have been made and schemes formulated to provide dwelling units to the slum dwellers for economically weaker sections with the State and Central assistance under Pradhan Mantri Awaas Yojna-Urban (PMAY-U). Shortage of funds has been cited as a constraint, it said.

The Centre on its part responded that out of 2.24 lakh houses in Maharashtra, 2 lakh were sanctioned for Mumbai alone, out of which 58,225 have been grounded, the rights panel said in its statement on Friday.

The Commission has sought a comprehensive report from the Secretary, Union Ministry of Housing and Urban Affairs. He has been given four weeks' time, the statement said.

The Union Ministry of Housing and Urban Affairs vide its communication dated December 3 2021, "submitted that the land and colonisation are State subjects".

Quoting the communication, the rights panel said the Centre is aug State t of eco

National Human Rights Commission-Online Media

Human Rights News

Mumbai: NHRC expresses concern over conditions of slum dwellers

https://www.freepressjournal.in/mumbai/mumbai-nhrc-expresses-concern-over-conditions-of-slum-dwellers

The National Human Rights Commission (NHRC) has expressed serious concern over the living conditions of slum dwellers in Mumbai. Acting on a complaint in this regard, the commission recently issued notices to the Maharashtra government and the Union Ministry of Housing and Urban Affairs seeking their responses.

In its response, the state government, through its Chief Secretary, has said that several efforts have been made and schemes formulated to provide dwelling units to slum dwellers with the state and Central assistance under the Pradhan Mantri Awas Yojna (Urban), PMAY (U).

However, shortage of funds has been cited as a constraint. The Centre, on its part, has responded that out of 2.24 lakh housing units in Maharashtra, two lakh were sanctioned for Mumbai alone, out of which 58,225 have been grounded. Vide its communication dated December 3, 2021, the ministry submitted that land and colonisation are state subjects, and the Centre is augmenting the efforts of the state to meet the housing needs.

Meanwhile, the NHRC has sought a response from the Secretary of the ministry to submit a comprehensive report within four weeks. Satish Lokhande, the CEO of the Slum Rehabilitation Authority (SRA), said that the basic needs of slum dwellers are taken care of by the municipal corporation and the Mumbai slum improvement board of MHADA. He said, “Funds from the housing department, slum improvement board and legislators are utilised for toilets, water, good roads and electricity.

The SRA’s job is to implement housing schemes in these declared slum clusters.” Lokhande said that in just one year his office has given approval to 1.5 lakh houses and a letter of intent has been issued. “Astonishingly, in the last 25 years of SRA’s history only two lakh houses were given. It is a milestone which we have achieved,” he said.

महाराष्ट्र सरकार को नोटिस: एनएचआरसी मुंबई के झुग्गियों में रहने वालों की स्थिति को लेकर चिंतित

https://www.bhaskarhindi.com/city/news/nhrc-concerned-over-condition-of-slum-dwellers-in-mumbai-329497

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोविड महामारी की सबसे बड़ी मार हाशिए पर मौजूद गरीब तबके को ज्यादा सहनी पड़ी। कोरोना की पहली-दूसरी लहर के बाद अब जब देश तीसरी लहर का सामना कर रहा है, तब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुंबई में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों की रहने की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। आयोग ने मामले में महाराष्ट्र सरकार और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया है। इससे पहले पिछले साल जून में एक अधिवक्ता राधाकांत ने एनएचआरसी में एक याचिका दायर कर कहा था कि सड़क पर लाखों बच्चों सहित लाखों बेघर लोग लंबे समय से वायरस और उसके बाद के लॉकडाउन उपायों के कारण बेहद पीड़ित है। इस याचिका पर विचार करते हुए एनएचआरसी ने कोविड-19 महामारी के दौरान बेघर लोग और बच्चे, लाखों लोगों की दुर्दशा पर गृह, स्वास्थ्य और आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों से जवाब मांगा था।

केन्द्र ने अपनी ओर से बीते 3 दिसंबर 2021 को दिए जवाब में भूमि और उपनिवेश को राज्य के विषय बताते हुए कहा कि पीएमएवाई-यू के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रुप से कमजोर व र्गों की आवास जरुरतों को पूरा करने के लिए राज्य के प्रयासों को बढा रहा है। साथ ही बताया कि महाराष्ट्र में 2.24 लाख घरों में से 2 लाख अकेले मुंबई के लिए स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 58,225 को बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र ने भी अपने सचिव के माध्यम से जवाब दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), पीएमएवाई (यू) के तहत राज्य और केंद्रीय सहायता के साथ आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को आवास इकाइयां प्रदान करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं और योजनाएं तैयार की गई है।

आयोग ने शुक्रवार को अपने एक बयान में में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों की रहने की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकारों ने जवाब में धन की कमी को एक बाधा के रुप में पेश किया गया है। आयोग ने इसे चिंतनीय बताते हुए मामले में दोनों सरकारों से चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।

Mumbai के झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के रहन-सहन की स्थिति को लेकर एनएचआरसी चिंतित

https://samacharnama.com/states/maharashtra-news/nhrc-concerned-over-living-conditions-of-slum-dwellers-in/cid6192110.htm

महाराष्ट्र न्यूज डेस्क !!! राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मुंबई में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों की रहने की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और महाराष्ट्र सरकार और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। महाराष्ट्र ने अपने मुख्य सचिव के माध्यम से जवाब दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), पीएमएवाई (यू) के तहत राज्य और केंद्रीय सहायता के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को आवास इकाइयां प्रदान करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं और योजनाएं तैयार की गई हैं। एनएचआरसी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि धन की कमी को एक बाधा के रूप में पेश किया गया है।

केंद्र ने अपनी ओर से जवाब दिया कि महाराष्ट्र में 2.24 लाख घरों में से 2 लाख अकेले मुंबई के लिए स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 58,225 को बंद कर दिया गया है। आयोग ने व्यापक रिपोर्ट देने के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव से जवाब मांगा है।आयोग ने कहा कि उन्हें चार सप्ताह का समय दिया गया है।केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 3 दिसंबर, 2021 को अपने संचार में प्रस्तुत किया कि भूमि और उपनिवेश राज्य के विषय हैं। केंद्र प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य के प्रयासों को बढ़ा रहा है।

इससे पहले पिछले साल जून में, मानवाधिकार कार्यकर्ता अधिवक्ता राधाकांत त्रिपाठी द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करते हुए, एनएचआरसी ने कोविड-19 महामारी के दौरान बेघर लोग और बच्चे, लाखों लोगों की दुर्दशा पर गृह, स्वास्थ्य और आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों से जवाब मांगा था। कार्यकर्ता की दलील में कहा गया है कि सड़क पर लाखों बच्चों सहित लाखों बेघर लोग लंबे समय से वायरस और उसके बाद के लॉकडाउन उपायों के कारण बेहद पीड़ित हैं।

HITAVADA, Nagpur, 9.1.2022
Page No. 4, Size:(14.43)cms X (10.52)cms.

NHRC expresses concern over living conditions of Mumbai slum dwellers, seeks report from Centre

NEW DELHI, Jan 8 (PTI)

THE National Human Rights Commission has expressed concern over the living conditions of slum dwellers in Mumbai and sought a "comprehensive report" from the Centre, officials said on Friday.

In a statement, the NHRC said that acting on a complaint in this connection, it had issued notices to the Government of Maharashtra and the Union Ministry of Housing and Urban Affairs seeking their responses.

The Government of Maharashtra responded, through its Chief Secretary, that several efforts have been made and schemes formulated to provide dwelling units to the slum dwellers for economically weaker sections with the State and Central assistance under Pradhan Mantri Awaas Yojna-Urban (PMAY-U). Shortage of funds has been cited as a constraint, it said.

The Centre on its part responded that out of 2.24 lakh houses in Maharashtra, 2 lakh were sanctioned for Mumbai alone, out of which 58,225 have been grounded, the rights panel said in its statement on Friday.